शब्दबाणों का प्रहार

मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय अखबार

सिवनी

राष्ट्रबाण

संपादक : संजय बघेल

मंगलवार 12 मई 2026 E-PAPER: www.rashtrabaan.in • वर्ष : 11 • अंक : 11 • पृष्ठ : 06 • मूल्य : 5.00 रुपए www.facebook.com/rashtrabaan www.twitter.com/rashtrabaan

न्यूज ब्रीफ

सौंदर्यीकरण-पुनर्विकास के लिए विशेष टास्क फोर्स बनी

नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आनंद विहार बस टर्मिनल के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई है। कोर्ट ने 26 मई तक प्लान पेश करने को कहा और पुलिस को अवैध वेंडिंग रोकने के निर्देश दिए। टास्क फोर्स में कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और 20 मई को पहली बैठक होगी।

गुजरात के आणंद में टेंपो ट्रक से टकराया, 4 की मौत; 5 घायल

सूरत। गुजरात के आणंद जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टेंपो के ट्रक से टकराने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। हादसा तारापुर-बगोदरा स्टेट हाईवे पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, टेंपो सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराया। मृतकों में एक 5 साल का बच्चा, दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। तारापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मयूर शर्मा ने बताया कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, टेंपो में सवार लोग दाहोद से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए तारापुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भारतीय सेना को दो स्वदेशी कॉम्बैट सिस्टम मिले

नईदिल्ली। भारतीय सेना ने दो नए स्वदेशी कॉम्बैट सिस्टम, यूएलपीजीएम और अग्निका वीटीओएल-1 को अपने हथियारों में शामिल किया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में इन्हें सेना को सौंपा गया। इन हथियारों का पहाड़ी इलाकों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी परिस्थितियों में सफल टेस्ट किया जा चुका है। ये सिस्टम पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं। इनमें शामिल यूपीएलजीरूहथियार को ड्रोन से लॉन्च किया जाता है और यह दिन-रात व हर मौसम में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। वहीं, अग्निका वीटीओएल -1 भारत का पहला 'कामिकेज' (आत्मघाती) ड्रोन है, जिसे शहरी इलाकों और कम जगह वाली जगहों पर सटीक हमले के लिए बनाया गया है।

राष्ट्रबाण

अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका लोकप्रिय अखबार राष्ट्रबाण तो आज ही अपने हॉकर से बोलिए या हमे कॉल कीजिए

सिर्फ 100 रुपए महीना

संपर्क : 7000427433

बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी

बंगाल की भाजपा सरकार का फैसला ; नए आपराधिक कानून लागू होंगे, आयुष्मान पर भी काम शुरू

राष्ट्रबाण | कोलकाता | एजेंसी
rashtrabaan.in

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

हावड़ा के नाबन्ना में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। सीएम अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने राज्य में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को लागू नहीं किया था। राज्य में अब बीएनएस लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएंगी। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निषिथ प्रमाणिक, क्षुदीराम और अशोक कीर्तनिया मौजूद थे। अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं।

चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के केस की जांच को भी तैयार

राजनीतिक हिंसा पर बोलते हुए, अधिकारी ने कहा कि अगर पीड़ित परिवारों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की, तो सरकार राजनीतिक संघर्षों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, 'हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान गई, अगर उनके परिवार चाहते हैं, तो सरकार जांच शुरू करेगी।'

सुवेंदु कैबिनेट की बैठक के फैसले

- चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसे 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र की सभी योजनाएं जल्द ही लागू होंगी। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं।
- आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी।
- बंगाल में बीएनएस लागू नहीं था, राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
- राज्य सरकार की नौकरियों में पांच साल का विस्तार दिया गया है।

बंगाल- मंत्रियों को विभाग बांटे : निषिथ को युवा कल्याण, अग्निमित्रा को महिला विकास मंत्रालय, दिलीप को पंचायती राज विभाग

पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार में सोमवार को विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम सुवेंदु अधिकारी के कैबिनेट में शामिल निषिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। पार्टी विधायक गौरिशंकर घोष के मुताबिक दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य मंत्रालय, क्षुदिराम टुडु को जनजातीय विकास और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रालय में शामिल एक मात्र महिला अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण और नगर पालिका मामले की कमान सौंपी गई है। आज नई सरकार की पहली प्रशासनिक बैठक के तुरंत बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया।

बांग्लादेश से लगती है बंगाल की 2216 किमी सीमा

भारत, बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है। सीएम अधिकारी ने दावा किया कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के खंड में से केवल लगभग 8 किलोमीटर के हिस्से को ही ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में फेंसिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है। 2021 में केंद्र सरकार ने बंगाल में बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था। यानी बीएसएफ 50किमी तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है। तत्कालीन ममता सरकार ने इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया था। दिसंबर 2021 में बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया था।

मप्र में फिलहाल शुरू नहीं होंगे परिवहन चेक पोस्ट

हाईकोर्ट ने लगाया स्टे; पिछले महीने दिया था इन्हें खोलने का आदेश

राष्ट्रबाण | भोपाल | एजेंसी
rashtrabaan.in

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज प्रदेशभर में बंद पड़े परिवहन (आरटीओ) चेक पोस्टों को दोबारा शुरू करने के अपने पूर्व आदेश पर स्टे (रोक) लगा दी है। इससे परिवहन क्षेत्र में हलचल मच गई है और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को राहत मिली है।

हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने 16 अप्रैल 2026 को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि सभी बंद चेक पोस्ट 30 दिनों के अंदर दोबारा चालू किए जाएं। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका और ओवरलोडिंग नियंत्रण से जुड़े मुद्दे पर दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि चेक पोस्ट बंद करने का 30 जून 2024 का सरकारी आदेश कोर्ट की पूर्व अंडरटेकिंग और 2018 के स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है। चेक पोस्ट सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग रोकथाम और परिवहन नियमों के पालन के लिए जरूरी हैं।

अब आगे क्या

चेक पोस्ट दोबारा खुलने से ओवरलोडिंग चेकिंग बढ़ने और कथित उत्पीड़न का डर था। वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। आज का स्टे उन्हें राहत देगा। परिवहन विभाग नई एसओपी (स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब स्थिति अनिश्चित हो गई है।

आज कोर्ट ने उसी ऑर्डर को स्टे कर दिया

आज हाईकोर्ट ने उसी आदेश पर स्टे दे दिया। इससे चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रुक गई है। यह फैसला संभवत: सरकार की अपील या संबंधित पक्षों की याचिका पर आया है। भोपाल के ट्रांसपोर्टर अमन भोंसले ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए स्टे ऑर्डर जारी किया गया है।

जुलाई 2024 से बंद हुए थे चेक पोस्ट

1 जुलाई 2024 से प्रदेश के अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बंद कर दिए गए थे। सरकार का तर्क था कि इससे परिवहन क्षेत्र को सुविधा मिलेगी और अनावश्यक चेकिंग से बचत होगी। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अप्रैल के अंत में कहा था कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी और लीगल ओपिनियन ले रही है।

टीएमसी 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

- कहा- यहां जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम, कोर्ट बोला- नई याचिकाएं लगाएं

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

सुप्रीम कोर्ट में टीएमसीने दावा किया कि बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर भाजपा और टीएमसी में हार जीत का अंतर एसआईआर में काटे गए वोटों से कम है। सोमवार को टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने यह बात जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच से कही। बेंच बंगाल में एसआईआर प्रैक्टिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेता बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के खिलाफ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

हार 862 वोटों से हुई, एसआईआर में 5000 वोट कम हुए

इससे पहले कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक मामले में उनके कैंडिडेट की हार 862 वोटों से हुई, जबकि उस सीट पर 5000 से ज्यादा वोटर नाम लिस्ट से हटाए गए थे। टीएमसी और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था और वोट डिलीशन के खिलाफ 35 अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सही उपाय श्वष्ट में याचिका दाखिल करना है।आयोग का कहना है कि एसआईआर और उससे जुड़े विवादों में इसी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही तय की जा सकती है।

बंगाल सीएम सुवेंदु के पीए हत्याकांड में 3 संदिग्ध गिरफ्तार

कोलकाता/पटना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बिहार और यूपी से 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को तीनों को नॉर्थ 24 परगना के बारासात कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इनमें दो युवक- मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर, जबकि राज सिंह को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शक है कि राज एक शार्पशूटर है।

जांच में सामने आया कि आरोपियों तक पहुंचने में टोल प्लाजा पर किया गया एक यूपीआई पेमेंट और सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा सुराग बना।

देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं : राहुल

- सोना न खरीदें, विदेश न जाएं जैसी 7 अपीलें उपदेश नहीं ; नाकामी के सबूत

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया 'सात अपीलों' पर पलटवार किया। उन्होंने इसे नाकामी करार दिया। कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया है।

एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा, 'कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं हैं। ये विफलता हैं।'

भारत में तेल के कुएं नहीं, पेट्रोल कम यूज करें

पीएम मोदी रविवार को कहा था, 'आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं।' पेट्रोल, गैस और डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है।

अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें। मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठाकर ले जाएं। हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए।

शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा।

उन्होंने कहा, '12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है। क्या खरीदें, क्या नहीं। कहां जाए, कहां नहीं।' दरअसल, रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा में पीएम मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण की रक्षा हो सके।

ट्रम्प ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकराया : बोले- मुझे पसंद नहीं आया

अमेरिका ने एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी

राष्ट्रबाण | तेल अवीव | एजेंसी
rashtrabaan.in

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।' इससे पहले भी ट्रम्प ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था।

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी।

अमेरिका ने इस हफ्ते ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। इसके बदले अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा, ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियां छोड़ेगा, साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने को तैयार नहीं है।

विश्वभर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतरीं, हम डटे रहे, डरे नहीं

पोकरण परमाणु परीक्षण पर मोदी बोले- दुनिया हिल गई थी

राष्ट्रबाण | जामनगर | एजेंसी
rashtrabaan.in

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा- आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज के ही दिन 11 मई 1998 को देश ने पोकरण में परमाणु परीक्षण किया था। तब दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतर गई थीं।

पीएम ने कहा- भारत के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। भारत ने पोकरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। क्योंकि शिव के साथ शक्ति आराधना ही हमारी परंपरा रही है। मैं भगवान सोमनाथ के चरणों में नमन करते हुए ऑपरेशन शक्ति की बधाई देता हूं।

वाजपेयी सरकार में हुआ था दूसरा परमाणु परीक्षण

11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। यह काफी गोपनीय ऑपरेशन था। इसकी तैयारियां इतनी गुप्त थीं कि विदेशी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इन परीक्षणों के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी रणनीतिक और वैज्ञानिक ताकत दिखाई।

पीएम बोले- भारत को कोई झुका नहीं सकता, 5 मुख्य बातें...

सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बन सकता, जब तक वह अपनी जड़ों से जुड़ा न रहे।

भारत में विरासत और आधुनिकता एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों साथ-साथ चलते हैं।

हमारे देश में सांस्कृतिक और पवित्र स्थलों के पुनर्निर्माण को लेकर काफी राजनीति हुई है। दुर्भाग्य से आज भी ऐसी ताकतें हैं, जो राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टिकरण को महत्व देती हैं।

लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर की भव्यता मिटाने की कोशिश की।

इस मंदिर को बार-बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ।

दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती और न ही दबा सकती है।

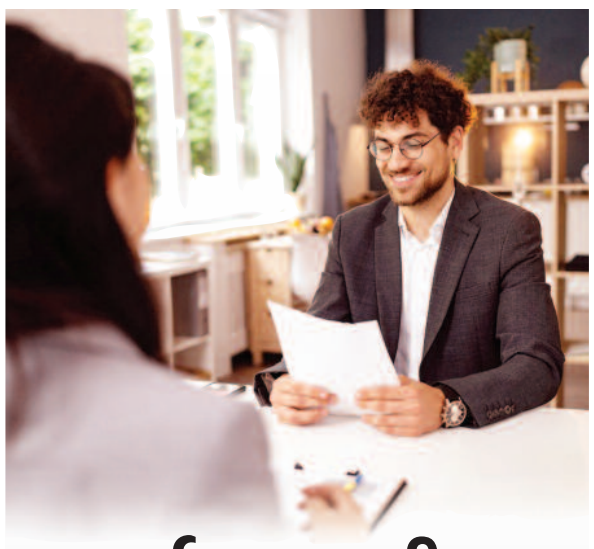

स्टार्टअप नहीं, बड़ी कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं युवा

आर्थिक अनिश्चितताओं और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामने आने वाली हालिया चुनौतियों के साथ, नौकरी चाहने वाले अब स्टार्टअप्स के बजाय बड़ी कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं.

नौकरी और पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना डॉट को के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 73 प्रतिशत नौकरी चाहने वाले संगठन के साथ काम करने और करियर में आगे बढ़ने के लिए स्थिर और स्थापित कंपनियों को पसंद करते हैं. रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक केवल 27 प्रतिशत कर्मचारी अभी भी करियर के विकास के लिए स्टार्टअप पर स्विच करने पर विचार करेंगे. अपना डॉट को के संस्थापक और सीईओ निरमित पारिख ने कहा, नौकरी चाहने वालों की बदलती प्राथमिकताओं के साथ भारत का नौकरी बाजार तेजी से विकसित हो रहा है. ऐसे में नौकरी चाहने वाले अब बेहतर करियर की संभावनाओं के लिए स्थिर और स्थापित कंपनियों की ओर अधिक झुकाव रखते हैं.

10 हजार नौकरी चाहने वालों से पूछे गए सवाल

रिपोर्ट तैयार करने के लिए में 10,000 से अधिक नौकरी चाहने वालों और 1,000 मानव संसाधन भर्तीकर्ताओं के बयानों को शामिल किया गया है. इसके मुताबिक नियोक्ता एक कौशल-प्रथम दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रहे हैं. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नौकरी चाहने वाले नौकरी की तलाश करते समय, स्थान, आने जाने और वर्क लाइफ बैलेंस और कंपनी की संस्कृति के साथ-साथ वेतन के साथ-साथ करियर के विकास के अवसरों को प्राथमिकता देते हैं. लगभग 73 प्रतिशत भारतीय अपनी नौकरी की खोज में करियर के विकास को प्राथमिक कारक मानते हैं. यहां तक कि वर्क लाइफ बैलेंस और लचीले काम के घंटों के महत्व को भी पार कर जाते हैं. 10 में से लगभग 9 नियोक्ताओं ने कुशल पेशेवरों के महत्व को भर्ती के लिए एक प्रमुख मानदंड के रूप में पहचाना है, हालांकि 10 में से केवल 6 नियोक्ताओं ने अपने संगठनों में अपस्किलिंग कार्यक्रमों को लागू किया है. इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि नियोक्ता अब तकनीकी कौशल वाले उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भूमिकाओं के लिए. लगभग 65 प्रतिशत पेशेवर नौकरी के साक्षात्कार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल को एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं.

स्टार्टअप्स में नौकरी जाने का डर

रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं प्रासंगिक कौशल पर अधिक जोर देती हैं, 77 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने 51 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में इसके महत्व का संकेत दिया है. नौकरी के लिए बड़ी कंपनियों को चुनना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि लोग छंटनी से बचना चाहते हैं क्योंकि हाल के दिनों में स्टार्टअप्स में छंटनी तेजी से बढ़ी है. स्टार्टअप कवरेज पोर्टल इंक42 ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की थी. उसके मुताबिक देश में अब तक 84 स्टार्टअप द्वारा 24,256 कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है. कर्मचारियों को बर्खास्त करने वाले स्टार्टअप्स की सूची देश में बढ़ती ही जा रही है.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में खास है नीदरलैंड

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हुए इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को देखना हॉलैंड में अध्ययन के लिए शायद सबसे बड़ी खासियत है, जिसे नीदरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। सब कुछ से परे, हॉलैंड को शिक्षा के मामले में दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसमें 2,100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें पढ़ाया जा रहा है और उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। यहां के कुछ सबसे लोकप्रिय शहरों में एम्स्टर्डम, वेल्प, हरलेम, ड्रोन्टेन, एसेन आदि शामिल हैं।

नीदरलैंड आपको सुंदर परिदृश्य और सीखने और अध्ययन के लिए बहुसांस्कृतिक समुदाय का एक समृद्ध मिश्रण प्रदान करता है। यहां रहने और अध्ययन की लागत अधिकांश अन्य यूरोपीय देशों के बराबर है, लेकिन आपके द्वारा चुने गए विश्वविद्यालय या कार्यक्रम के आधार पर इसे कम किया जा सकता है। शीर्ष हॉस्टल यहां स्थित हैं और अतिथि आवास के रूप में कुछ आवास प्रदान करते हैं या यहां तक कि बाहर के परिसर में से एक में साझा कमरे भी हैं।

छात्रवृत्ति

यहां छात्रवृत्ति और अनुदानित शिक्षा प्राप्त करने की प्रणाली अपेक्षाकृत आसान है। डच उच्च शिक्षा सब्सिडी वाली है और ट्यूशन फीस अपेक्षाकृत कम है। यूरोपीय संघ के छात्रों के लिए वार्षिक ट्यूशन फीस लगभग व 1,950 से शुरू होती है। जो गैर-यूरोपीय संघ के देशों से आते हैं, स्नातक कार्यक्रमों के लिए औसत ट्यूशन शुल्क 6,000 और 15,000 के बीच हो सकता है, एक मास्टर कार्यक्रम के लिए वे 8,000 और 20,000 के बीच हो सकते हैं। इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में छात्रवृत्ति विभिन्न विश्वविद्यालयों और यहां तक कि कुछ निजी कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध हैं। यहाँ उपलब्ध सामान्य छात्रवृत्ति विकल्पों की एक सूची इस प्रकार है-

- शैक्षणिक अनुसंधान छात्रवृत्ति
- एम्स्टर्डम मेरिट स्कॉलरशिप
- कैनन फाउंडेशन रिसर्च फैलोशिप
- सीईयू प्रेशिडियम लिबर्टीटिस छात्रवृत्ति
- जापान / विश्व बैंक स्नातक छात्रवृत्ति कार्यक्रम
- लीडेन विश्वविद्यालय उत्कृष्टता छात्रवृत्ति कार्यक्रम
- मार्टेन वैन हेंगेल ऋण कार्यक्रम
- मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी हॉरर छात्रवृत्ति के शहर
- छात्रवृत्ति अटलांटिस
- स्कॉलरशिप बीकास मागदालेना ओ। वडा। डी ब्रॉकमैन
- छात्रवृत्ति अनुदान अनुबंध - एफओएनसीओ
- टीयू डेल्फ़ एक्सेलेंस स्कॉलरशिप - इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंजीनियरिंग
- टीयू डेल्फ़्ट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप - डीआरआई इन्फ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी
- यूनिवर्सिटी ऑफ़ ट्वेंटी स्कॉलरशिप
- वेबस्टर विश्वविद्यालय गेटवे छात्रवृत्ति

हॉलैंड में शिक्षा प्रणाली

हॉलैंड में शिक्षा की एक द्विआधारी प्रणाली है। इसका अर्थ है कि आप दो प्रकार की शिक्षा में से किसी एक को चुन सकते हैं अनुसंधान-उन्मुख शिक्षा, अनुसंधान विश्वविद्यालयों द्वारा पेशकश की। उच्च पेशेवर शिक्षा, लागू विज्ञान के विश्वविद्यालयों द्वारा पेशकश की। उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में से एक में प्रवेश के लिए, किसी को संस्थान से संपर्क करने और अपनी पसंद के कार्यक्रम पर लागू होने वाली सटीक प्रवेश आवश्यकताओं का पता लगाना होगा। अधिकांश स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, आपको उचित स्तर पर माध्यमिक-स्कूल डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्थान का अलग-अलग मापदंड होता है। हालांकि, एक छोटा राष्ट्र होने के नाते हमेशा बहुत सारे आवेदक होते हैं और कोटा वास्तव में तेजी से भरा जाता है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए, किसी को स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष प्राप्त करना होगा। आप देखेंगे कि आप अपनी पसंद का डिप्लोमा चुन सकते हैं और यह उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर देखा जा सकता है।

भाषा आवश्यकताएँ

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना अनिवार्य है। अधिकांश विश्वविद्यालय अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य कर देते हैं। आईईएलटीएस और टीओईएफएल आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन कुछ कैम्ब्रिज अंग्रेजी के लिए भी जांच कर सकते हैं। टीओईएफएल के लिए आवश्यक स्कोर कम से कम 550 (पेपर आधारित) या 213 (कंप्यूटर आधारित) हैं। आईईएलटीएस के लिए कम से कम 6 का स्कोर आवश्यक है। कुछ कार्यक्रमों की अलग-अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं।

प्रारंभिक वर्ष

कुछ मामलों में, विश्वविद्यालय आपके लिए स्नातक या मास्टर पाठ्यक्रम लेने से पहले कुछ अतिरिक्त तैयारी करना अनिवार्य कर सकता है। इसे तैयारी वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। डच उच्च शिक्षा संस्थान आपको सशर्त स्वीकृति पत्र प्रदान करता है। डच आव्रजन कानून के अनुसार, आप अपनी पढ़ाई से पहले अधिकतम एक वर्ष के लिए नीदरलैंड में आने के लिए योग्य हैं ताकि प्रारंभिक पाठ्यक्रम का पालन किया जा सके और संस्था द्वारा निर्धारित परीक्षाओं को पास किया जा सके। उसी को पूरा करने पर, आप तब स्वीकृति का सशर्त पत्र प्राप्त कर सकते हैं जिसे स्वीकृति के निश्चित पत्र में बदल दिया जाता है।

तीन चक्र

2002 में हॉलैंड ने स्नातक की मास्टर डिग्री की शुरुआत की। हालाँकि, अभी भी दो प्रकार की शिक्षा के बीच एक अंतर मौजूद है। यह अनुसंधान विश्वविद्यालयों और अनुप्रयुक्त विज्ञान के विश्वविद्यालयों दोनों में उपलब्ध है। एक स्नातक की डिग्री (पहला चक्र) प्राप्त कर सकता है, फिर आप मास्टर डिग्री (दूसरा चक्र) के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर कार्यक्रम को पूरा करने के बाद आप पीएचडी डिग्री या पीडीएएन डिग्री प्रोग्राम (तीसरा चक्र) शुरू कर सकते हैं।

लोकप्रिय पाठ्यक्रम

इंजीनियरिंग

प्रमुख इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तकनीकी डिजाइनर कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं जिनमें उन्नत अध्ययन और कई इंजीनियरिंग क्षेत्रों में एक व्यक्तिगत डिजाइन कार्य शामिल है। तकनीकी डिजाइनर कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 2 साल हैं और स्नातकों को इंजीनियरिंग में व्यावसायिक डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होती है।

अनुसंधान

उन्मुख स्नातक कार्यक्रमों तक पहुंचने के लिए, छात्रों को एक वीडब्ल्यूओ डिप्लोमा होना चाहिए या लागू विज्ञान के विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम के पहले वर्ष (60 क्रेडिट) को पूरा करना होगा। छात्रों के बाद की श्रेणी में, अतिरिक्त चयन मानदंड लागू हो सकते हैं। लागू विज्ञान के विश्वविद्यालयों में न्यूनतम पहुंच आवश्यकता या तो एक डिप्लोमा या माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा (एमबीओ) का डिप्लोमा है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।

कृषि और पर्यावरण

आप पर्यावरण विज्ञान, बायोसिस्टम्स इंजीनियरिंग, समुद्री जीवन, पशु विज्ञान, ग्रामीण विकास और इसी तरह के कई अन्य विकल्पों में पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। कृषि विज्ञान में परास्नातक डिग्री भी है जो आपको अंतर्निहित और जटिल कारकों को समझने की क्षमता प्रदान करता है, जो कृषि प्रणालियों को परिभाषित करने में मदद करते हैं। इसके माध्यम से आप वैज्ञानिक सिद्धांतों और विश्लेषणात्मक कौशल में ठोस आधार प्राप्त कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र से बहुत अधिक राजस्व और यहां खेती और कृषि के बहुत सारे अवसरों के साथ, कोई भी आसानी से एक ऐसे पाठ्यक्रम में उद्यम कर सकता है जो दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है।

प्रबंधन

हॉलैंड में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रबंधन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज (बीबीए) कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण के साथ-साथ मास्टर्स में भी समान पाठ्यक्रम शामिल हैं। पाठ्यक्रम आपको एक अंतरराष्ट्रीय वातावरण में काम करने और एक उद्यम के उच्च व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सह-जिम्मेदार होने की पेशकश करता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ प्रबंधन के संयोजन के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठा के साथ, यह सुनिश्चित है कि प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए एक शानदार जगह है।

खेल

खेल हॉलैंड में प्रोत्साहित किया जाता है और इसे विश्वविद्यालय स्तर पर भी पढ़ाया जाता है। मूल रूप से पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान से लेकर सिद्धांत कक्षाओं तक सब कुछ शामिल है। इन कोर्सेज को करने से फिजिकल फिटनेस, कोचिंग, थेरेपी और अन्य विषयों के मिश्रण के बारे में भी जान सकते हैं जो कि खेल विज्ञानों पर केंद्रित हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों के साथ, अपनी खुद की एक लीग लेकर, आप पाएंगे कि यहां लेने के लिए ढेर सारे विकल्प हैं।

कंप्यूटर विज्ञान

कंप्यूटर विज्ञान यहाँ और अन्य जगहों पर बहुत मांग में है। औसतन, यहां काम करने वाले पेशेवर एक वर्ष में लगभग 23,144 यूरो कमाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान और इसके आवेदन पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री शामिल हैं, साथ ही हॉलैंड की कुछ बेहतरीन कंपनियों में इंटर्नशिप प्राप्त करने का अवसर भी है। एक बहुसांस्कृतिक देश होने के नाते कई आगामी संस्थान हैं जो यहां व्यावहारिक और सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों का मिश्रण पेश करते हैं। पाठ्यक्रम के जोर में व्यवस्थित प्रक्रियाओं (जैसे एल्गोरिदम) का अध्ययन करना शामिल है ताकि अधिग्रहण, प्रतिनिधित्व, प्रसंस्करण, भंडारण, संचार और सूचना तक पहुंच की सहायता की जा सके। कंप्यूटर विज्ञान प्रक्रियाओं की व्यवहार्यता, संरचना, अभिव्यक्ति और मशीनीकरण के विश्लेषण पर छात्रों को बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करना है। वे पायथन और सी, हास्केल, जावा और पास्कल जैसी भाषाओं में दक्षता हासिल करते हैं।

राष्ट्रबाण
सिवनी, मंगलवार 12 मई 2026

बालाघाट राष्ट्रबाण

● बैहर ● बिरसा ● कटंगी ● तिरोड़ी ● कटंगी ● खैरलांजी ● किरनापुर ● लालबर्रा ● लांजी ● परसवाड़ा ● वारासिवनी

बालाघाट में गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: 48 मवेशी मुक्त, 6 आरोपी जेल भेजे गए

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की सूचना पर लालबर्रा पुलिस का आधी रात ऑपरेशन, 6 पिकअप वाहन जब्त, मवेशियों को गौशाला भेजा गया

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में गौवंश तस्करी विगत कई वर्षों से अवैध रूप से चलते आ रही है। जिसकी शिकायत भी जिम्मेदार प्रशासन को की जाती है। किंतु जिम्मेदार प्रशासन जागरूक लोगों के द्वारा सूचना करने और साथ में रहने पर जिम्मेदार प्रशासन कार्यवाही करता है। राजनीति सत्ता पक्ष व विपक्ष के जनप्रतिनिधि नेताओं से भी यह अवैध गौ वंश तस्करी का विषय छुपा हुआ नहीं है लेकिन सत्ता पक्ष या विपक्ष भी इन गौ वंश के वाहनों में अवैध तरीके से परिवहन व मवेशियों को काटने के लिए कत्लखाने महाराष्ट्र व अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है जिसकी जानकारी सभी दलों के नेताओं को है लेकिन इस अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल के नेता कोई पहल नहीं करते हैं और चुनाव के पहले गौ माता व अन्य मुद्दों को लेकर भोली भाली जनता को बहला फुसला कर अपने पक्ष में करने का काम करते हैं।

गौ वंश (मवेशियों बैल) की तस्करी का ऐसा ही एक मामला 9 मई शनिवार की मध्यरात्रि में प्रकाश में आया है। जहां बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सूचना एवं जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के साथ में रहने पर बालाघाट जिले की लालबर्रा पुलिस ने लालबर्रा के आमाटोला पुरानी हरडे मिल के पास व रिजवान के गोदाम के पास उसी की प्लाटिंग व उपजाऊ भूमि में रस्सी से बंधे हुए 21 नग मवेशी (बैल) व 6 पिकअप वाहन में 27 मवेशी बैल पुलिस ने बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कत्लखाने जाने से गौ तस्करों से छुड़ाए, तथा पुलिस ने सुबह होते ही 6 पिकअप वाहन व 6 ड्राइवर एवं 48 नग मवेशियों को जप्त कर थाना परिसर में लाया।

जहां पुलिस कर्मियों ने सभी मवेशियों को पानी पिलाया। पशु चिकित्सकों द्वारा सभी मवेशियों का मुलाहिजा किया गया। पुलिस ने 48 नग मवेशियों को चंदोरी वारासिवनी गौशाला पहुंचाया एवं 6 पिकअप वाहन को जप्त कर एवं उनके ड्राइवर व मालिक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह सभी 6 पिकअप वाहन के ड्राइवर व मालिक बालाघाट जिले के रजेगांव किरनापुर क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस द्वारा इस मामले में और भी जांच पड़ताल की जा रही है। यह अवैध गौ वंश (मवेशियों बैल) तस्करी का माल किसका था ? इसका मुख्य सरगना मुख्य बोस कौन है ? यह अभी ज्ञात नहीं हुआ है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है।

यदि जिम्मेदार पुलिस प्रशासन का समस्त अमला अवैध गौ तस्करी के खिलाफ सख्त हो जाए और मुख्य आरोपी पर ठोस कार्रवाई करें एवं सभी हिंदूवादी संगठनों के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस अवैध तस्करी मामले पर एकजुट होकर सक्रिय रहें तो गौ तस्करी की अनैतिक गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। हिंदूवादी संगठनों के कुछ सक्रिय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की सक्रियता के चलते गौ वंश तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कुछ कार्यवाही भी की है। किंतु गौ तस्करी से जुड़े मुख्य सरगना मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच नहीं पाती है। यही कड़ी अवैध गौ वंश तस्करी के खिलाफ उनकी कमर तोड़ने में कमजोर साबित हो रही है। सरकार को कत्लखानों को ही बंद करवा देना चाहिए।

पुलिस ने जप्त किए सभी 6 पिकअप वाहनों को राजसात करने की तैयारी

वाहन क्रमांक एमएच 20 ईजी0182, एमपी41 जीए 6019, एमपी50 जी 1473, सीजी 04 एनएच 4339, एमएच 35 एजी 5522, एमएच 20 डीई 6448, इन नंबरों की गाड़ियां इस अवैध गौ तस्करी के कार्य में संलिप्त थी। जिन्हें पुलिस राजसात करने की तैयारी में है। लालबर्रा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि सूचना पर हमारे द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर 6 पिकअप वाहन से 27 नग गौवंश मवेशी बैल व 21 नग मवेशी बैल रस्सी से बंधे हुए पकड़ा गया है, जिन्हें कत्लखाना महाराष्ट्र की ओर ले जाने की योजना थी, हमारे द्वारा 48 नग गौवंश मवेशी बैल व 6 पिकअप वाहन उनके ड्राइवर को पकड़ा गया है। पशु क्रूरता अधिनियम व मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है एवं इस अवैध गौ तस्करी के कार्य में जुड़े हुए सभी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है।

हिंदूवादी संगठनों ने निभाई सक्रिय भूमिका

हिंदूवादी संगठनों से जुड़े गौवंश प्रेमी व गौवंश रक्षक ने भी बताया कि सूचना मिलने पर एसपी साहब को अवगत कराकर थाना प्रभारी के साथ आमाटोला मौका स्थल पर पहुंचे। जहां चावड़ी के पास से एक कंटेनर में भी संभवत : काले जानवर भरकर कंटेनर को सिवनी की ओर रवाना कर दिया गया। जहां 6 पिकअप वाहन में 27 नग गौवंश (मवेशी बैल) व खाली स्थान पर रस्सी में बंधे हुए 21 नग गौ वंश (मवेशी बैल) गौ तस्करों से छुड़ाए गये। अवैध गौ वंश तस्करी करने वाले गौ तस्कर गौ वंश मवेशियों को कत्लखाना महाराष्ट्र की ओर ले जाते हैं। जिम्मेदार प्रशासन अनैतिक गतिविधियों से जुड़े हुए मुख्य लोगों को पकड़े और उन पर ठोस कार्रवाई करें, तब ऐसी अनैतिक गतिविधियों पर विराम लग सकेगा। ठोस कार्यवाही निरंतर होते रहनी चाहिए। हम सभी लोगों का नैतिक दायित्व है कि हम सभी लोग गौ वंश मवेशियों की सुरक्षा के लिए आगे आयें। आगे भी मुख्य गौ तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए अन्यथा सभी संगठन जिम्मेदार प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

थाना में प्रकरण पंजीबद्ध

थाना लालबर्रा में अपराध क्रमांक 182/26, धारा 4,6,9 मध्यप्रदेश गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, धारा 6 (क), 7, 10 मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार 6 आरोपियों को न्यायालय पेश कर भेजे गये जेल भेजा गया। इनमे देवेंद्र खरे आयु 22 वर्षीय निवासी ग्राम नक्शी किरनापुर, अतुल नागवंशी आयु 23 वर्षीय निवासी ग्राम बोदा किरनापुर, दिलीप कुशे आयु 36 वर्षीय निवासी रजेगांव किरनापुर, सिद्धार्थ वैध आयु 29 वर्षीय निवासी रजेगांव किरनापुर, अश्विन भोयर आयु 23 वर्षीय निवासी ग्राम बोदा किरनापुर व विदेशी खरे आयु 32 वर्षीय निवासी ग्राम नक्शी किरनापुर है। सभी आरोपियों को लालबर्रा पुलिस ने वारासिवनी न्यायालय में पेश कर जेल में दाखिल करा दिया है।

गोलमाल है भाई... सब गोलमाल है!

500 का नोट या राजनीतिक पटकथा?

विधायक अनुभा मुंजारे के भाषण ने खोल दी 'कल्पना राजनीति' की पोल

कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसी नेता।

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट विधानसभा की विधायक अनुभा मुंजारे एक बार फिर अपने भाषणों को लेकर सवालों और विवादों के केंद्र में आ गई हैं। मंच से भावनात्मक कहानियां सुनाकर तालियां बटोरने की राजनीति अब जनता की नजरों में सवाल बनती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए उनके हालिया बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के कार्यक्रम में विधायक ने दावा किया कि जब वे आठवीं कक्षा में पढ़ती थीं तब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जबलपुर स्थित उनके स्कूल पहुंचे थे और उनके गीत से प्रभावित होकर उन्हें 500 रुपये का नोट पुरस्कार में दिया था।

लेकिन भाषण खत्म होते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर उस समय 500 रुपये का नोट था कहां? बस फिर क्या था... सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बयान को 'फिल्मी स्क्रिप्ट', 'भावनात्मक ड्रामा', 'राजनीतिक अभिनय' और 'कल्पना की राजनीति' बताकर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया।

जनता पूछ रही है कि क्या अब कांग्रेस में राजनीति तथ्यों और जमीनी कामों से नहीं बल्कि काल्पनिक कहानियों और भावनात्मक पटकथाओं से चलेगी? क्या कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अब इतिहास भी बदला जाएगा? कांग्रेस के अंदर भी इस बयान को लेकर नाराजगी और फुसफुसाहट तेज हो गई है। कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन पहले ही कमजोर दौर से गुजर रहा है, ऊपर से ऐसे बयान पार्टी की बची-खुची विश्वसनीयता को भी खत्म करने में लगे हैं।

इतना ही नहीं, आरोप यह भी लग रहे हैं कि विधायक एक तरफ भावनात्मक अंदाज में लोगों को फुसलाने और सहानुभूति बटोरने का प्रयास करती हैं, तो दूसरी तरफ मौका मिलते ही वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से भी नहीं चूकतीं। ताजा मामला स्वागत समारोह का बताया जा रहा है, जहां लालबर्रा के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को मंच से यह कहकर जलील किया गया कि मेरे बंगले पर उपस्थित न होकर यहां आने का समय मिल गया। इस टिप्पणी के बाद कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई और इसे वरिष्ठ नेताओं के आत्मसम्मान पर चोट माना जा रहा है।

अनुभा मुंजारे, विधायक बालाघाट : आधी हकीकत, आधा फ़साना, अब ऐसी राजनीति का जमाना।

क्या ? मानसून से पहले पूरी तरह तैयार हो जाएगी सड़क

लालबर्रा – समनापुर सड़क का मामला

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट जिले के लालबर्रा बस स्टैंड से लेकर समनापुर की ओर जाने वाला लगभग 600 मीटर मार्ग अधूरा था,जिसे बनाने के लिए लगातार वार्ड वासियों, क्षेत्रीय जनों की मांग पर मीडिया कर्मियों ने समय-समय पर उनकी आवाज को बुलंद करते हुए मामला जिम्मेदार प्रशासन के संज्ञान में लाया।

इसके बाद स्थानीय विधायक के प्रयासों से उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। लेकिन पानी निकासी और विद्युत पोलों की शिफ्टिंग, ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग को लेकर यह मार्ग विवादों में रहा, जिससे महिनों से चल रहा है यह 600 मीटर का मार्ग अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि सड़क निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है लेकिन सड़क पर पड़ने वाला बाक्स कलवर्ट पुलिया अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है केवल पुरानी पुलिया तोड़ दी गई है और रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिससे लग रहा है कि जल्दी ही इस पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, अब देखना यह होगा कि क्या ? मानसून आने के पहले यह पुलिया बनकर तैयार हो पाता है या नहीं। इसके अलावा विद्युत पोलों और ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का काम भी बाकी है । फिलहाल नाली निर्माण का काम प्रगति पर दिखाई दे रहा है। वार्ड वासियों सहित क्षेत्रीय जनों ने बरसात से पहले सड़क को पूरी तरह तैयार करने की मांग की है।

कागजों में हरियाली,जमीनी हकीकत में उजड़ा जंगल!

● लाखों के वृक्षारोपण पर उठे सवाल ● मौके पर सूखी झाड़ियां और कटे पेड़ों के निशान

वन विभाग के दावों की खुली पोल,ग्रामीणों व वन प्रेमियों में आक्रोश

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

पर्यावरण संरक्षण,हरियाली बढ़ाने और जंगलों को समृद्ध बनाने के नाम पर वन विभाग हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर बड़े-बड़े वृक्षारोपण अभियान चलाने के दावे करता है,सरकारी रिपोर्टों में हजारों पौधे लगाए जाने और जंगलों को हरा-भरा बनाने की तस्वीरें पेश की जाती हैं,लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो विभागीय दावों की परतें खुद-ब-खुद उधड़ने लगती हैं।

बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र के खैरगोंदी बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक 442 में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां वर्ष 2020-21 में किए गए वृक्षारोपण कार्य की वास्तविक स्थिति ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थल पर लगे जंग खाए बोर्ड में साफ उल्लेख है कि विभाग द्वारा लगभग 700 हेक्टेयर क्षेत्र में 3900 (तीन हजार नौ सौ)पौधों का वृक्षारोपण किया गया था। लेकिन मौके पर न तो हरियाली दिखाई देती है और न ही हजारों पौधों का कोई अस्तित्व नजर आता है। जहां घने वृक्ष और विकसित जंगल होना चाहिए था,वहां सूखी झाड़ियां,बंजर जमीन और कटे हुए पेड़ों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर पेड़ों पर कुल्हाड़ी के निशान साफ नजर आ रहे हैं,जिससे यह आशंका और गहरा जाती है कि वृक्षों का बड़े पैमाने पर अवैध कटान भी हुआ है।

ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हर साल लाखों पौधे लगाने का दावा करता है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि केवल कागजों में वृक्षारोपण दिखाकर शासन की राशि का बंदरबांट किया जाता है और बाद में पौधों की सुरक्षा तथा देखरेख की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण बताया गया है,वहां आज भी वीरानी पसरी हुई है। यदि वास्तव में हजारों पौधे लगाए गए होते और समय पर उनकी सुरक्षा,सिंचाई एवं निगरानी की जाती,तो आज यह क्षेत्र घने जंगल के रूप में विकसित हो चुका होता।

वन विभाग पर संरक्षण नहीं, लापरवाही के आरोप

पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों का कहना है कि यदि विभाग वास्तव में जंगल बचाने और हरियाली बढ़ाने के लिए गंभीर होता,तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। पौधों की नियमित निगरानी,सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था होती तो आज यह क्षेत्र हरियाली से आच्छादित दिखाई देता। लेकिन मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि विभागीय लापरवाही,निगरानी की कमी और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण शासन की महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण योजनाएं दम तोड़ रही हैं।

अब जांच और कार्रवाई की मांग तेज

ग्रामीणों व वन प्रेमियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वृक्षारोपण कार्य की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से लाखों रुपये की योजना धरातल पर विफल हुई है,उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूत्रों के अनुसार अब मीडिया कर्मियों की टीम जल्द ही विधिवत अनुमति लेकर जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाने की तैयारी कर रही है।यदि ऐसा हुआ तो वन विभाग के कई और चौंकाने वाले तथ्य उजागर हो सकते हैं।

सवालों के घेरे में विभागीय कार्यप्रणाली

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर लाखों रुपये खर्च कर लगाए गए हजारों पौधे गए कहां? यदि पौधे लगाए गए थे तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हुई? यदि पौधे नष्ट हो गए तो उसकी जवाबदेही किसकी तय की गई? ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विभाग केवल बोर्ड लगाकर औपचारिकता पूरी कर देता है, जबकि मौके पर वास्तविक कार्य नाममात्र का होता है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी क्षेत्र में हरियाली नजर नहीं आती।

मीडिया कवरेज पर भी आपत्ति!

हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान का मामला सामने आया है,उसके किनारे से बोरीटोला-मजार-साल्हे मार्ग को जोड़ने वाला लगभग एक किलोमीटर लंबा आम रास्ता बना हुआ है,जिससे प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीणों का आना-जाना होता है। ग्रामीणों को इस रास्ते से गुजरने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी मार्ग से गुजरते समय मीडिया कर्मी की नजर वृक्षारोपण स्थल पर पड़ी,जहां उजड़े हुए वृक्ष और कटान के निशान देखकर उन्होंने रुककर कवरेज किया। लेकिन आरोप है कि इसके बाद संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा इसे अपराध बताने का प्रयास किया गया। अब यह सवाल भी उठने लगा है कि जब गांव से लगे और सड़क किनारे स्थित सागौन वृक्षारोपण की यह स्थिति है,तो जंगल के भीतर मौजूद बहुमूल्य और विशालकाय वृक्ष कितने सुरक्षित होंगे?

बालाघाट में पुलिस को चकमा देकर शराब तस्कर फरार

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट की गढ़ी थाना पुलिस ने सोमवार को एक कार से 57.240 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस चेकिंग को देखकर तस्कर वाहन समेत भाग निकला और बाद में कार को खेत में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बैहर की ओर से एक सिल्वर रंग की कार (सीजी04एच3606) में अवैध शराब ले जाई जा रही है। खुर्सीपार खजरा तिराहे पर जब पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, तो चालक चेकिंग पॉइंट पार कर पास के गांव की ओर भागने लगा। इसके बाद पुलिस के पीछा करने पर आरोपी वाहन को गांव के बाहर एक खेत में छोड़कर भाग गया। गढ़ी थाना प्रभारी योगेश कुमरे ने बताया कि जब लावारिस मिली कार की तलाशी ली गई, तो उसमें से अंग्रेजी शराब के 7 कार्टून मिले। बरामद शराब की कुल मात्रा 57.240 लीटर मापी गई है। पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है।

सवा दो लाख का सामान जब्त: जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 63,918 रुपए और कार की कीमत करीब 1.64 लाख है। इस कार्रवाई में एएसआई चंदनलाल तेलासे सहित आरक्षक नागवेन्द्र पांडे, शुभम सेन और अन्य पुलिसकर्मियों की मुख्य भूमिका रही। पुलिस फरार आरोपी की पहचान के लिए वाहन स्वामी के दस्तावेजों की जांच कर रही है।

राष्ट्रबाण
सिवनी, मंगलवार 12 मई 2026

सिवनी राष्ट्रबाण

● बरघाट ● छपारा ● धनोरा ● घंसौर ● केवलारी ● कुरई ● लखनादौन ● सिवनी ग्रामीण

कृषि विस्तार अधिकारी मनीराम मरावी के संरक्षण में किसानों से हो रही खुली लूट

शिक़ायत पर कार्यवाही के स्थान पर व्यापारियों के मुनाफे की करते हैं चिंता !, केवलारी में 266.50 रु.की यूरिया को 300 रु.में खरीदने को मजबूर हो रहे किसान, उसके साथ भी क्रय करना पड़ता है अनावश्यक सामग्री

कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हैं एसएडीओ मनीराम मरावी

राष्ट्रबाण केवलारी| संवाददाता
rashtrabaan.in

एक ओर भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिले के कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे या यू कहे उनके ही संरक्षण में किसानों के साथ सरेआम ठगी का खेल जारी है। ताज़ा मामला सिवनी जिला की केवलारी तहसील से यूरिया खाद की कालाबाजारी का सामने आया है, जहाँ निर्धारित मूल्य 266.50 रुपये वाली यूरिया की बोरी धड़ल्ले से 300 रु.से 320 रुपये में बेची जा रही है। हैरानी की बात यह है कि किसानों ने आरोप लगाया कि इस पूरी 'खुली लूट' को कथित तौर पर स्थानीय कृषि अधिकारियों जिसमें विशेष कर श्रेष्ठ मनीराम मरावी का संरक्षण प्राप्त है।

267 रु.की बोरी 300 रु. में बेचने का कृषि अधिकारियों के संरक्षण में व्यापारी बना रहे दबाव ?

केवलारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम आलोनीखापा निवासी शिकायतकर्ता कृषक मोईन कुरैशी और महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्होंने शासन की ऑनलाइन टोकन व्यवस्था के तहत खाद के लिए विधिवत बुकिंग की थी। दिनांक 11 मई 2026 को जब वे केवलारी आईएफएफडीसी केएसके केंद्र पर पहुँचे, तो केंद्र संचालक विवेक अग्रवाल द्वारा उनसे यूरिया खाद की शासकीय दर 267 .रु प्रति बोरी के स्थान पर 300 रु .की मांग की गई। किसानों का आरोप है कि अधिक मूल्य देने से मना करने पर उन्हें खाद उपलब्ध कराने में अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, एवं खाद नहीं दी गई।

पीड़ित कृषकों ने केवलारी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दर्ज किया शिक़ायत

पीड़ित कृषकों ने केंद्र संचालक विवेक अग्रवाल एवं सादो मनीराम मरावी के विरुद्ध वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही की मांग को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जहां से केवलारी के संवेदनशील स्शरूमहेश अग्रवाल जी द्वारा जांच कर दोषियों के खिलाफ़ उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि किसानों ने इस शिकायत की एक प्रतिलिपि सिवनी जिले की बेहद संवेदनशील कलेक्टर, को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस खुलेआम हो रही कालाबाजारी और विभागीय मिलीभगत पर क्या कड़ा कदम उठाता है या गरीब और मजबूर किसान ऐसे ही, बड़े और रसूखदार व्यापारी एवं अधिकारियों की लुट का शिकार होते रहेंगे यह तो समय की गर्त में छिपा है।

विवेक अग्रवाल, व्यापारी : अफसरों की यारी, किसानो से लूट पर भारी।

कृषि विकास अधिकारी पर संरक्षण देने का आरोप !

मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू संबंधित कृषि अधिकारी मनीराम मरावी का रवैया रहा । किसानों ने जब इस अवैध वसूली की शिकायत कृषि विकास अधिकारी मनीराम मरावी से की, तो समाधान के बजाय उन्होंने कथित तौर पर कहा कि, 'व्यापारी के साथ सामंजस्य बनाकर चलो, व्यापारी यदि यूरिया 300 रुपये की नहीं देगा तो धंधा कैसे करेगा' ? उसे बचत क्या होगी? किसानों का कहना है कि इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना जवाब से स्पष्ट होता है कि विक्रेता को विभागीय संरक्षण प्राप्त है या आशंका यह भी है कि किसानों से हो रही खुलम खुला अवैध वसूली में एक मोटी हिस्सेदारी उनकी भी हो।

नेहा मीणा, कलेक्टर : किसानो से लूट करने वालो पर चाबुक चलाओ मैडम।

> शिकायत प्राप्त हुई है कि केवलारी के एक खाद बीज व्यापारी विवेक अग्रवाल द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया का विक्रय कर रहा है, जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
>
> -महेश अग्रवाल एसडीएम केवलारी ।

सुस्त सिस्टम पर बरसीं अपर कलेक्टर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

फाइलें दौड़ाओ या कार्रवाई के लिए तैयार रहो !

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक महज एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि सुस्त अधिकारियों के लिए अल्टीमेटम साबित हुई। अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत ने साफ कर दिया कि जनता की शिकायतों और शासन की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का दौर अब खत्म होना चाहिए।

बैठक में जब सीएम हेल्पलाइन के 50 और 100 दिनों से लंबित प्रकरणों का कच्चा चिट्ठा खुला, तो मैडम के तेवर कड़े हो गए। उन्होंने कड़क शब्दों में कहा कि सिर्फ फाइलें मत घुमाओ, शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निराकरण करो। जिन शिकायतों में काम मुमकिन नहीं, उन्हें लटकाने के बजाय फोर्स क्लोज के लिए भेजो। सीपी ग्राम और सीएम हेल्पलाइन पर जनता की संतुष्टि ही अधिकारियों की रिपोर्ट कार्ड तय करेगी।

जनगणना और शिक्षा : घर-घर जाओ, डेटा लाओ!

जनगणना 2027 को लेकर अपर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मकान सूचीकरण में एक भी घर या परिवार छूटना नहीं चाहिए। लापरवाही बरतने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों पर गाज गिरना तय है। साथ ही शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि दफ्तरों से निकलकर घर-घर जाकर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।

जर्जर भवन और अनुकंपा नियुक्ति, हादसों का इंतजार क्यों?

अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत ने विभाग प्रमुखों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि जर्जर और अनुपयोगी भवनों को ध्वस्त करने में देरी क्यों हो रही है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? उन्होंने तत्काल ऐसी इमारतों की लिस्ट मांगी है। वहीं, अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को भावनाओं से जोड़ते हुए उन्होंने इसे प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए।

गेहूं उपार्जन, किसानों को परेशान किया तो खैर नहीं!

उपार्जन केंद्रों पर अव्यवस्था की खबरों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को मैदानी निरीक्षण के लिए दौड़ाया है। साफ निर्देश हैं कि किसान की उपज का एक-एक दाना सुगमता से खरीदा जाए, बिचौलियों या अव्यवस्था की जगह जेल होनी चाहिए। प्रशासन अब वेट एंड वॉच के मूड में नहीं है। अपर कलेक्टर की इस सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो अधिकारी समय सीमा में काम करें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह और अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप सहित तमाम विभाग प्रमुख मौजूद थे।

कुपोषण और सिकल सेल, कागजों पर नहीं, फील्ड पर दिखे काम

स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान तीखे सवाल हुए। जब बच्चे कुपोषित हैं, तो एनआरसी केंद्र खाली क्यों? केंद्रों को क्षमता के अनुसार भरें और बच्चों का इलाज करें। पात्र मरीजों की पेंशन और यूडीआईडी कार्ड के काम में सुस्ती पर उन्होंने नाराजगी जताई और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर नेहा मीना मिड करियर ट्रेनिंग पर

सिवनी। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सिवनी जिले की कलेक्टर नेहा मीना का चयन प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आयोजित मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किया गया है। यह उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई 2026 से 05 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें मीना अपनी सहभागिता दर्ज करेंगी।

अनिल कुमार राठौर को मिला अतिरिक्त प्रभार

नेहा मीना की प्रशिक्षण अवधि के दौरान जिले के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के अधिकारी अनिल कुमार राठौर को कलेक्टर सिवनी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अनिल राठौर वर्तमान में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में कार्यकारी संचालक के पद पर कार्यरत हैं। शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, अनिल राठौर प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सिवनी जिले के कलेक्टर का उत्तरदायित्व भी संभालेंगे।

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

कृष्ण लालचंदानी, नवागत पुलिस अधीक्षक : कुरई थाने में पसरी नशे की गंदगी की सफाई की जरुरत।

क्या नए कप्तान साफ करेंगे कुरई की गंदगी या चलती रहेगी वसूली एक्सप्रेस?

जिले के पुलिस महकमे में इन दिनों हलचल तेज है। एक तरफ नए पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने कमान संभाली है, तो दूसरी तरफ कुरई थाना अपनी काली कारगुजारियों के कारण उनके स्वागत में कड़वाहट घोल रहा है। चर्चा गरम है कि कुरई में कानून का राज नहीं, बल्कि वसूली तंत्र का सिक्का चलता है। विश्व प्रसिद्ध पेंच नेशनल पार्क, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अब कुरई पुलिस की कथित मूक सहमति से नशे के सौदागरों और गौवंश तस्करों का स्वर्ग बन चुका है। आरोप बेहद गंभीर हैं, कहा जा रहा है कि कुरई थाना प्रभारी कृपाल टेकाम की नाक के नीचे शराब, गांजा और चरस की डोर तो डोर डिलीवरी हो रही है। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाएं, तो जनता की पुकार सुनने वाला कोई नहीं बचता।

नए 'कप्तान' के लिए ये चुनौतियां

-जनता के बीच अब बस एक ही सवाल तैर रहा है कि क्या पुलिस अधीक्षक कुरई थाने की इस नीलामी को रोक पाएंगे?
-क्या भ्रष्टाचार की इस बेलगाम एक्सप्रेस पर कोई ब्रेक लगेगा?
-क्या वर्दी की चमक फिर से बहाल होगी, या वसूली के रुपयों की धूल इसे और फीका कर देगी?

फाइलें दुरुस्त, पर नीयत में खोट?

कुरई की सड़कों पर दौड़ते गौवंश से लदे ट्रक इस बात की चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं कि खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। सूत्रों की मानें तो यहाँ पुलिस का ध्यान अपराध रोकने पर कम और महीना कलेक्शन फिक्स करने पर ज्यादा है। वही स्थानीय निवासी का साफ कहना है कि साहब को फोन लगाना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि वे कुछ खास लोगों का ही फोन उठते हैं और मुलाकातों और कलेक्शन 'के गणित में व्यस्त रहते हैं।

सिस्टम की सर्जरी की दरकार

जब रक्षक ही फाइलों के आंकड़े दुरुस्त करने में जुट जाएं, तो बर्बाद होती युवा पीढ़ी और बेजुबान मवेशियों का दर्द किसे सुनाई देगा? अब देखना यह है कि चाबुक वाली कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले नए कप्तान साहब कुरई थाने की इस गंदगी को साफ करने के लिए कितनी तेजी से अपना चाबुक चलाते हैं।

जनगणना कार्य का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण

समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

जिला प्रशासन द्वारा जनगणना 2027 के अंतर्गत चल रहे मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य की गंभीरता से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में रविवार 10 मई को अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी सुनीता खण्डायत तथा संभागीय प्रभारी अधिकारी सुधीर कुमार ने नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का दौरा कर जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान टीम ने बुधवारी क्षेत्र की विभिन्न प्रगणक ब्लॉकों में पहुँचकर प्रगणकों और सुपरवाइजरों से सीधे चर्चा की और कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अधिकांश क्षेत्रों में लगभग 70 से 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि, एचएलबी क्रमांक 46 में कार्य की गति धीमी मिलने पर अपर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित चार्ज अधिकारी को अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य को गति देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गणना का कार्य न केवल समय पर पूरा होना चाहिए, बल्कि इसमें डेटा की शुद्धता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

अपर कलेक्टर सुनीता खण्डायत ने तकनीकी बारीकियों पर जोर देते हुए कहा कि एकत्रित किए गए डेटा को पूरी तरह जांचने और संतुष्ट होने के बाद ही पोर्टल पर सिंक किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे। इस दौरान अतिरिक्त जनगणना अधिकारी एस.आर. मरावी, शुभम श्रीवास्तव मुख्य नगरपालिका अधिकारी विशाल सिंह मस्कोले सहित अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि जिले में यह गणना अभियान 1 मई से प्रारंभ हुआ है जो 30 मई 2026 तक निरंतर जारी रहेगा।

प्रेस क्लब सिवनी में तानाशाही के आरोप, बिना स्पष्टीकरण सदस्य का निष्कासन

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

प्रेस क्लब ऑफ सिवनी (प्रेस एसोसिएशन) द्वारा हाल ही में कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ सदस्य अखिलेश दुबे की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय को लेकर विवाद गहरा गया है। संस्था के इस कदम को लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं और इसे एकतरफा व न्याय-संगत प्रक्रिया के विरुद्ध बताया जा रहा है।

इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे संस्था की गरिमा के प्रतिकूल बताया गया है। विरोध जता रहे सदस्यों का मानना है कि इस कार्रवाई में नियमों और पारदर्शिता की पूरी तरह अनदेखी की गई है।

निष्पक्ष जांच की मांग

प्रेस क्लब के अन्य जागरूक सदस्यों और पत्रकार जगत ने मांग की है कि न्याय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए। साथ ही, लगाए गए आरोपों की किसी निष्पक्ष समिति से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

निष्कासन पर उठाए गए मुख्य बिंदु

-पक्ष रखने का नहीं मिला मौका : शिकायत है कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर की गई इस बड़ी कार्रवाई से पहले संबंधित सदस्य को अपना पक्ष रखने या स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
-अपारदर्शी कार्यप्रणाली : सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्री दुबे द्वारा किस प्रकार की अनुशासनहीनता की गई थी। बिना किसी ठोस कारण या सार्वजनिक विवरण के सदस्यता समाप्त करना संस्था की साख पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
-व्यक्तिगत द्वेष की आशंका : उचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि संभवत: अध्यक्ष और सचिव द्वारा यह निर्णय व्यक्तिगत रंजिश या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर लिया गया है।

एसडीओपी अपूर्व भलावी को के.एफ.रुस्तम जी परम विशिष्ट पुरस्कार से विभूषित

साहस और कर्तव्यनिष्ठा को मिला सम्मान

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

मध्यप्रदेश पुलिस के शौर्य और रणनीतिक कौशल की परंपरा को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सिवनी जिले के लखनादौन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपूर्व भलावी को उनकी अदम्य वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित के. एफ. रुस्तम जी पुरस्कार 2021-22 की सर्वोच्च परम विशिष्ट श्रेणी से सम्मानित किया गया है।

11 मई को राजधानी में आयोजित एक गरिमामय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपूर्व भलावी को रिवॉल्वर एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनकी कर्तव्यपरायणता की सराहना की।

सीएम मोहन यादव से के.एफ.रुस्तम जी पुरस्कार लेते हुए एसडीओपी अपूर्व भलावी।

अपूर्व भलावी को यह सम्मान उनकी जिला बालाघाट पदस्थापना के दौरान नक्सल उन्मूलन क्षेत्र में किए गए साहसिक कार्यों के लिए दिया गया है। अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के विरुद्ध कई प्रभावी मोर्चों का नेतृत्व किया। अपूर्व भलावी ने माओवादी संगठन के सक्रिय और खूंखार सदस्य संदीप की गिरफ्तारी के लिए एक जटिल और जोखिम भरा अभियान चलाया। दुर्गम जंगलों और कठिन परिस्थितियों की परवाह न करते हुए, उन्होंने उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। संदीप की गिरफ्तारी न केवल एक अपराधी की पकड़ थी, बल्कि इससे माओवादी संगठन की भविष्य में होने वाली कई हिंसक वारदातों और साजिशों के मंसूबों को समय रहते नाकाम कर दिया गया।

अपूर्व भलावी को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने की खबर जैसे ही लखनादौन पहुँची। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। विभाग के सहयोगियों ने इसे उनकी मेहनत और निष्ठा का परिणाम बताया है। इस सम्मान के साथ अपूर्व भलावी ने यह सिद्ध कर दिया है कि पुलिस बल का असली गहना उसकी वर्दी नहीं, बल्कि वह साहस है।

क्या है के.एफ. रुस्तम जी पुरस्कार?

यह पुरस्कार मध्यप्रदेश पुलिस के संस्थापक और आधुनिक भारतीय पुलिसिंग के स्तंभ माने जाने वाले श्री के.एफ. रुस्तम जी की स्मृति में दिया जाता है। यह सम्मान उन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना असाधारण साहस दिखाते हैं। इसकी परम विशिष्ट श्रेणी अत्यंत दुर्लभ और सर्वोच्च मानी जाती है। अपूर्व भलावी की यह उपलब्धि न केवल अनुविभाग लखनादौन पुलिस बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी इस सफलता से युवा पुलिस अधिकारियों को समाज सेवा और कानून व्यवस्था के प्रति समर्पित रहने की नई ऊर्जा मिलेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक संजय बघेल द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एमपी नगर भोपाल म.प्र से मुद्रित कराकर शिवनगर कॉलोनी सड़क मोहल्ला मरझोर जिला सिवनी से प्रकाशित।
RNI NO.: MPHIN/2015/72804 , **संपादक*** **संजय बघेल** पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र सिवनी होगा। E-mail: rashtrabaan@gmail.com. mob: 7000427433